

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5306
उत्तर दिनांक 25/03/2026 को दिया गया

नाभिकीय विद्युत क्षमता का विस्तार

5306. डॉ. आलोक कुमार सुमन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) निर्माणाधीन रिएक्टरों सहित वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस संबंध में अपनाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वर्ष 2030 तक प्राप्त की जाने वाली निर्धारित लक्ष्य क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) वर्तमान स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 8.78 गीगावाट (आरएपीएस-1 को छोड़कर) है। वर्तमान में 3500 मेगावाट क्षमता के पांच पीएचडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं और 5600 मेगावाट क्षमता के आठ पीएचडब्ल्यूआर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। कुल 4000 मेगावाट की क्षमता के चार पीडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक क्रमिक पूर्ण करने की योजना है।
इसके अलावा, भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना का कमीशनन कर रही है।
- (ख) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं - जैसे कि स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है।
- (ग) भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए असैन्य नाभिकीय सहयोग हेतु 18 देशों के साथ अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (घ) वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के क्रमिक पूर्ण होने पर वर्ष 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।
